छोटे उद्यमों के जरिये गांवों में आर्थिक विकास ला रही है माइक्रो ग्रिड

सैकंड आर्टिकल

एनर्जी

प्रवीर सिन्हा

सीईओ व एमडी, टाटा पावर

Twitter: @praveer_sinha

भारत आज पांचवां सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश है और इसकी स्थापित क्षमता लगभग 3.35 लाख मेगावॉट है। अप्रैल 2017 और जनवरी 2018 के बीच देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1,003.52 अरब यूनिट्स थी और इसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। सरकार अक्षय ऊर्जा में 1,75,000 मेगावॉट उत्पादन की योजना के साथ स्वच्छ विद्युत उत्पादन क्षमताओं के लिए भी दरवाजे खोल रही है। देश में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत अभी भी दुनिया की औसत खपत की लगभग एक तिहाई है। इसके बावजूद वितरण के स्तर पर बिजली की कुल क्षति करीब 22 फीसदी है। इसका समाधान माइक्रो ग्रिड जैसी नई उत्पादन क्षमताओं में है। इनके जरिये हमने ग्रामीण क्षेत्रों में 95 फीसदी लक्षित परिवारों तक पहुंच बना ली है। देश में लगभग 1.05 करोड़ परिवार अभी भी पावर ग्रिड्स के दायरे से बाहर हैं। ऐसे में माइक्रोग्रिड उम्मीद जगाते हैं। ये पावर इकोसिस्टम को अधिक दक्ष बनाते हैं। जैसे ग्रिड का कोई हिस्सा रखरखाव या मरम्मत के लिए बंद हो तो माइक्रोग्रिड से जुड़े अस्पताल या स्कूल बदस्तूर चलते रह सकते हैं।

गोल्डमैन सैश सेंटर फॉर एन्वायर्नमेंटल मार्केट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की माइक्रो-ग्रिड क्षमता 2019 तक 90 मेगावॉट तक पहुंचने की संभावना है और इसके लिए लगभग 1,800 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। हमने बिहार के दो गांवों में दो मिनी-ग्रिड प्रोजेक्ट्स लागू किए हैं, जिससे लगभग दो हजार की आबाद को लाभ मिलेगा। इसकी एक परियोजना तयाबपुर में है, जो वैशाली का बिजली रहित गांव है। दूसरा सोलर माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट बिजली रहित बेहलोपुर गांव में है, जो वैशाली जिले में गंगा नदी में एक टापू पर है। इस परियोजना को मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एनर्जी एंड एन्वायर्नमेंटल पॉलिसी रिसर्च के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही जनरल इलेक्ट्रिक के सहयोग से एक स्वचालित एकीकृत एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम भी विकसित किया गया है।

हम बिहार के सिवान जिले में ज्ञानी मोरे गांव में एक और मिनी-ग्रिड लागू कर रहे हैं। माइक्रो-आंत्रप्रेन्योर्स जैसे कृषि सेवाएं, थोक में दूध को ठंडा रखने के संयंत्र और रिवर्स ऑस्मोसिस वॉटर सिस्टम्स के साथ एक मिनी-ग्रिड स्थापित की जा रही है, जिससे ऐसा बिज़नेस मॉडल निर्मित होगा, जो आर्थिक विकास के साथ ग्रामीण मिनी-ग्रिड को बढ़ावा देगा। इससे घरों एवं माइक्रो-आंत्रप्रेन्योर्स दोनों के लिए किफायती बिजली उपलब्ध होगी। नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने मई 2016 में नेशनल मिनी-माइक्रो ग्रिड पॉलिसी का मसौदा पेश किया था, जो मिनी/माइक्रो ग्रिड, तकनीकी मानदंड आदि में कुछ स्पष्टता देती है। हालांकि अभी यह लागू होना है। उत्तर प्रदेश में एक मिनी-ग्रिड पॉलिसी अपनाई गई है। अधिकांशतः सरकारी स्वामित्व वाले प्रादेशिक विद्युत मंडल माइक्रो ग्रिड्स को सुविधा से वंचित आबादी तक बिजली पहुंचाने की योजनाओं को पूरा करने के लिए श्रेष्ठ माध्यम के रूप में अपना सकते हैं।